भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2639

(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

2639. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:
श्री थिरु थंगा तमिलसेल्वन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान का मूल्यांकन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि , दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत देश में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कार्य-निष्पादन की नियमित आवधिक समीक्षा और महिला सशक्तीकरण में उनके योगदान का मूल्यांकन कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों , राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के साथ समीक्षाओं , प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के माध्यम से निगरानी, राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटरों द्वारा क्षेत्रीय दौरों और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष अनुसंधान संगठनों के माध्यम से योजनाओं के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है।

इसके अलावा, देश में स्वयं सहायता समूहों के योगदान और डीएवाई-एनआरएलएम के परिणामों को समझने के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन और आकलन अध्ययन किए गए हैः

1. इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन (3आईई) द्वारा 2019-20 के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में डीएवाई-एनआरएलएम का एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं:

- आय में वृद्धि: उपचार क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों की आय में आधार रेखा के सापेक्ष 19% की वृद्धि हुई।
- ऋण का औपचारिककरण: अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता में 20% की गिरावट आई, जो औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच का संकेत है।
- बचत वृद्धि: प्रतिभागियों ने बचत में 28% की वृद्धि की सूचना दी , जो मजबूत वित्तीय सामर्थ्य और संसाधन प्रबंधन को दर्शाता है।
- कार्यबल भागीदारी: श्रम बल जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई , नियंत्रण क्षेत्रों के सापेक्ष उपचार क्षेत्रों में द्वितीयक व्यवसायों की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं का अनुपात 4% अधिक था।
- सामाजिक योजनाओं तक पहुँच: उपचाराधीन परिवारों द्वारा लाभ उठाए गए सामाजिक कल्याण योजनाओं की संख्या में 6.5% की वृद्धि हुई (2.8 योजनाओं के आधार की तुलना में), जो लोक कल्याण कार्यक्रमों के बारे में बेहतर जागरूकता और पहुँच को दर्शाता है।

2. देश के विभिन्न क्षेत्रों के छह राज्यों (अरुणाचल प्रदेश , बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश) में 2024-25 में डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड (डीआरएस) द्वारा महिला किसानों की आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने में उनकी स्थिति को समझने के लिए एक अध्ययन किया गया। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं:

- महिला किसानों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: महिला किसानों के बीच कार्यक्रम के कथित लाभों में आत्मविश्वास में वृद्धि (48%), निर्णय लेने में सुधार और श्रम लागत में कमी (32%), कृषि ज्ञान में वृद्धि (40%), और उच्च अनाज उपज (52%) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम ने वार्षिक आय में वृद्धि में योगदान दिया , जिसमें भाग

लेने वाले 18% परिवारों ने वार्षिक आय में 7% से अधिक की अतिरिक्त वृद्धि की सूचना दी।

3. डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड (डीआरएस) द्वारा 2024 में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं:

- एसवीईपी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण: इस कार्यक्रम की एक उल्लेखनीय उपलब्धि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर इसका अधिक ध्यान है — 71% उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं — साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने में भी इसकी भूमिका है। लगभग 35% उद्यमी अपने एसवीईपी-सहायता प्रदत्त उद्यम शुरू करने से पहले किसी भी आय-उत्पादक गतिविधि में शामिल नहीं थे , और इनमें से लगभग 74% उद्यम अब घरेलू आय का प्राथमिक स्रोत बन गए हैं।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2023 में बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) सखी मॉडल की प्रभावशीलता पर एक अध्ययन शुरू किया, जिसका उद्देश्य इसके कार्यान्वयन ढांचे, प्रशिक्षण और तैनाती प्रक्रियाओं, प्रदान की जाने वाली सेवाओं और बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रामीण समुदायों दोनों पर इसके प्रभाव की जाँच करके मॉडल का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करना था। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं:

- अध्ययन में पाया गया कि 45% बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट सखियाँ डिजी-पे सखियों में परिवर्तित हो गई हैं, जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में उनकी क्षमताओं का विस्तार हुआ है। बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट सखियों की आय के स्तर और उनकी उद्यमशीलता से जुड़ाव के बीच संबंध के बारे में एक रोचक प्रवृत्ति सामने आई है। 61% से अधिक बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट सखियाँ पूरी तरह से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में अपनी भूमिका से प्राप्त आय पर निर्भर हैं। बीसी सखियाँ जो पूरी तरह से अपने बीसी एजेंट के रूप में अपनी भूमिका पर निर्भर करती हैं, आमतौर पर इस गतिविधि से अधिक कमाई करती हैं बजाए उन लोगों के जो अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाते हैं।

ये परिणाम डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत निरंतर और प्रभावी सहायता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक डेटा-समर्थित प्रमाण देते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।